की उस कमेटी को हमने भंग कर दिया और हमने उसके लिए 4 कैटेगरीज़ बना दीं। एक कैटेगरी हमने बनाई किसी भी कास्ट या रिलीजन के जो अनइम्प्लॉयेड यूथ हैं, उनके लिए। दूसरी कैटेगरी हमने शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राईब्ज़ के लोगों के लिए बनाई। तीसरी कैटेगरी हमने उनके लिए बनाई जो फिज़िकली इम्फर्म लोग हैं, विकलांग हैं। चौथी कैटेगरी हमने एक्स-आर्मीमैन के लिए बनाई है। हमने कहा कि इन्हीं 4 कैटेगरीज़ के बीच में पी.सी.ओ. का आवंटन होगा। हमने उसको ओपन कर दिया है इन कैटेगरीज़ के आधार पर। जो पी.सी.ओ. के आवंटन के लिए पहले कमेटी थी, उसको भंग कर दिया है। मैं समझता हूं कि इन चारों कैटेगरीज़ में हर जाति, हर समुदाय के लोग आ जाते हैं और एस.सी./एस.टी. के लोगों के लिए तो संविधान में ही प्रावधान है, तो ये सब लोग इसमें कवर हो जाते हैं। उनको इससे लाभ मिल रहा है और लाभान्वित लोगों की संख्या भी बढ़ रही है।

शिवडी-न्हावा-शेवा लिंक रोड और वैस्टर्न एक्सप्रैस हाइवे परियोजना को स्वीकृति दिया जाना

*162. **श्री सतीश प्रधान:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि शिवडी-न्हावा-शेवा लिंक रोड और वैस्टर्न एक्सप्रैस हाइवे (वरली से नरीमन प्वाइंट तक) से संबंधित प्रस्ताव योजना मंत्रालय के पास स्वीकृति हेतु लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कब विचार किया जाएगा; और

(ग) इस पर अब तक विचार न किए जाने के क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): (क) से (ग) प्रस्तावित मुबई ट्रांस हार्बर लिंक (शिवडी-न्हावा लिंक) का संरेखण मुबई पत्तन न्यास के विभिन्न प्रतिष्ठापनों से गुजरता है और इसलिए मुंबई पत्तन न्यास ने महाराष्ट्र सरकार के परियोजना प्राधिकारियों को इस परियोजना के संरेखण में परिवर्तन करने का सुझाव दिया था। मुंबई पत्तन न्यास को महाराष्ट्र सरकार से कोई और प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

महाराष्ट्र सरकार ने पश्चिम एक्सप्रैस राजमार्ग से संबंधित प्रस्ताव जल-भूतल परिवहन मंत्रालय को नहीं भेजा है।

Approval for Shivadi-Nhawa-Shewa Link Road and Western Express Highway Projects

†162. SHRI SATISHCHANDRA SITARAM PRADHAN: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

†Original notice of the Question was received in Hindi.

(a) whether Government are aware that the proposal regarding the Shivadi-Nhawa-Shewa Link Road and Western Express Highway (from Worli to Nariman Point) is lying pending with the Ministry of Planning for approval;

(b) if so, by when it will be considered; and

(c) the reasons for not considering it so far?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI RAJNATH SINGH: (a) to (c) The alignment of proposed Mumbai Trans Harbour link (Shivadi-Nhawa link) crosses various installations of Mumbai Port Trust and therefore, the Mumbai Port Trust had suggested change in the alignment of the project to the Project Authorities of the Government of Maharashtra. No further proposal from the State Government of Maharashtra has been received by the Mumbai Port Trust.The proposal regarding Western Express Highway has not been referred to the Ministry of Surface Transport by the Government of Maharashtra.

श्री सतीश प्रधान : सभापति महोदय, मुंबई में न्हावा-शेवा का जो बंदरगाह है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से कंटेनर और बल्क ट्रैफिक बहुत बड़ी तादाद में होता है। यहां से आयात भी होता है और निर्यात भी बहुत बड़ी मात्रा में होता है। मारुति मोटर्स का सब एक्सपोर्ट यहां से हुआ करता है तो न्हावा-शेवा का बंदरगाह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब बोधे इंजीनियर थे तब एक प्लान बनाया गया था कि गेटवे ऑफ इंडिया से न्हावा-शेवा को कनेक्ट किया जाए। उसके बाद दोबारा इस पर विचार हुआ और शिवडी से न्हावा-शेवा को कनेक्ट करने का प्लान बनाया गया था। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया कि इस प्लान का रि-ऐलाइनमेंट करने की आवश्यकता है।

महाराष्ट्र में जब शिव सेना और भाजपा की सरकार थी और मुख्य मंत्री मनोहर जोशी जी थे। तब यह रि-एलाइंमेंट के प्रपोजल के लिए भी हां भरा गया। अभी फिर से रि-एलाइंमेंट को प्रपोजल बनाया गया है, तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाह रहा हूं कि यह बार-बार रि-एलाइंमेंट की बात चल रही है इसकी वजह से जो ऑरिजनल प्रपोजल था तब की कीमत क्या थी और रि-एलाइंमेंट के बाद क्या कीमत हो गई और आज की तारीख में रि-एलाइंमेंट करके जो नया प्रपोजल बनाया है उससे और कितनी कीमत बढ़ने वाली है, इस विषय पर हमको जानकारी दें?

श्री राजनाथ सिंह: माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं कि यह दोनों परियोजनाएं महाराष्ट्र सरकार की परियोजनाएं हैं, केन्द्र सरकार की यह परियोजनाएं नहीं हैं। यह सच है कि आज से तीस वर्ष पूर्व 1970 में ही मुम्बई में जनसंख्या का दबाब और सड़कों के ऊपर ट्रैफिक डेंसिटी बढ़ने के कारण मुम्बई में लगातार कंजेक्शन बढ़ रहा था। उस

कंजेशन को कम करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने यह विचार किया था कि शिवडी–न्हावा–शेवा रोड बनाई जाए और 1970 से 13 वर्षों के बाद 1983 और 1984 में जाकर इसको अंतिम रूप दिया था लेकिन यह प्रस्ताव इस समय हमारे मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है। यह सच है कि 26 मई, 1998 को महाराष्ट्र सरकार ने मिनिस्ट्री आफ एंवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट को एंवायरनमेंट क्लीयरेंस के लिए भेजा था। लेकिन मिनिस्ट्री और एंवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट को जितनी पर्याप्त सूचनाएं चाहिए थी उतनी सूचनाएं महाराष्ट्र सरकार ने नहीं भेजी। इसलिए मिनिस्ट्री आफ एंवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने उस प्रस्ताव को पुनः पर्याप्त सूचना भेजने के लिए महाराष्ट्र सरकार को वापिस कर दिया। सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि इसमें पहली परियोजना जो शिवडी–न्हावा परियोजना है इस संबंध में तो एक प्रस्ताव निश्चित रूप से प्राप्त हुआ था लेकिन जो दूसरी परियोजना है वेस्टर्न - एक्सप्रेस हाइवे की, वह हमारे मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुई है।

श्री सतीश प्रधान: सर, बात ऐसी है कि अभी पूरे महाराष्ट्र में इस विषय की चर्चा है और अखबारों में भी खबर छप रही है कि महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने इस परियोजना को स्टे–आर्डर दिया तथा वह कोई भी नई परियोजना होने नहीं देना चाहते। इसीलिए मैं जानना चाहूंगा कि आपने जैसा बताया कि हमारी जानकारी ऐसी भी है कि यह शिवडी–न्हावा–शेवा का जो प्रोजेक्ट है - वरली से नरीमन प्वाइंट का, यह मिनिस्ट्री आफ प्लानिंग के पास पैंडिंग पड़ा हुआ है तो इस विषय में क्या सच परिस्थिति है और क्या इसके ऊपर महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने स्टे–आर्डर देकर यह काम बंद करके रखा है, इस विषय पर बताएं?

श्री राजनाथ सिंह: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा था उस प्रश्न में उन्होंने यह जानकारी चाही थी कि क्या इस परियोजना का प्रस्ताव प्लानिंग कमीशन के पास लम्बित है? लेकिन चूंकि यह प्रश्न मेरे विभाग में पहुंच गया था, मैंने कहा कि इसकी जानकारी प्राप्त की जाए क्योंकि इसका उत्तर मैं स्वयं देना चाहूंगा ताकि सही सूचना माननीय सदस्य को प्राप्त हो सके। जो हमारे पास सूचना है ऐसा कोई भी प्रस्ताव प्लानिंग कमीशन के समक्ष लम्बित नहीं है। मिनिस्ट्री आफ एंवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने जैसा मैंने पहले कहा कि महाराष्ट्र सरकार के इस प्रस्ताव को मिनिस्ट्री को पर्याप्त सूचना भेजने के लिए वापिस कर दिया है। लेकिन मैं यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि 1980 में एक जो दूसरा पोर्ट ट्रस्ट है जिसे जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहते हैं उसके साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक कमिटमेंट था। यह ठीक है कि इस जे॰एन॰पी॰टी॰ का आप निर्माण कीजिए लेकिन किसी भी नए ब्रिज का अथवा किसी नए काज्वे का निर्माण महाराष्ट्र सरकार नहीं करेगी। लगता यह है कि इधर महाराष्ट्र सरकार ने जरूर विचार किया है कि इस प्रोजेक्ट का काम प्रारम्भ किया जाना चाहिए। इसीलिए मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट से उन्होंने अनुरोध किया था कि जो हमारा कमिटमेंट था 1980 में कि हम किसी ब्रिज अथवा किसी काज्वे का

निर्माण नहीं करेंगे कृपया इसमें रिलेक्सेशन दी जाए अथवा उनका कहना था कि यह जो शर्त थी इस शर्त का मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट वापिस लेने के लिए तैयार हो जाए।

मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट की अपनी मजबूरी है। मजबूरी यह है कि जो पीरपाऊ में वहां पर बर्थ बनी हुई है और वहां पर अन्य बर्थें भी इस समय बन गई हैं। वहां केमीकल बर्थ और कोल बर्थ बनी हुई हैं तो यदि वहां पर इस प्रोजेक्ट का निर्माण हो जाता है तो इससे कारगो हैंडलिंग बाधित होगी। यह भी सच है कि मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट ने पहले यह कहा था कि यदि नई बर्थ हमारी बन जाती है तो हम पुरानी बर्थों को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन बाद में कंसलटैंट्स ने यह सुझाव दिया कि कारगो हैंडलिंग जो प्रतिदिन बढ़ती जा रही है उसके लिए पुरानी बर्थ की आवश्यकता होगी। इसलिए मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट ने यह अनुरोध किया कि जो पुरानी परियोजनाएं हैं उनके रि-एलाइनमैंट के बारे में महाराष्ट्र सरकार विचार करे।

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Mr. Chairman, Sir, I would like to know from the hon. Minister whether this Western Express Highway touches Rajasthan also. If so, which are the towns covered? If not, do you have any Express Highway plan for Rajasthan?

श्री राजनाथ सिंह: सभापति महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि यह परियोजना पूरी तरह से राज्य सरकार की परियोजना है। इसलिए अब यह राजस्थान को टच करती है या नहीं करती है इसके संबंध में इस समय मुझे पूरी जानकारी नहीं है। माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं इसकी सूचना उन्हें उपलब्ध करा दूंगा।

श्री ओंकार सिंह लखावत: सभापति महोदय, इस एक्सप्रेस हाईवे परियोजना की प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की थी। उन्होंने लगभग 7,300 किलोमीटर लम्बे मार्ग की घोषणा की और यह कहा कि यह देश में अदभुत किस्म का एक हाइवे बनेगा। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पिछले वित्तीय वर्ष में केवल 220 किलोमीटर के लिए कुछ राशि स्वीकृत हुई थी, तो बाकी 7,300 किलोमीटर को आप कब तक पूरा कर देंगे और उसके लिए इस वर्ष आप कितनी धनराशि देने वाले हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी राजस्थान इंदिरा गांधी नहर की तरह ही इसका भी वही हाल बन जाएगा। यह मैं आपसे जानना चाहता हूं।

श्री राजनाथ सिंह: सभापित महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है। लेकिन यदि आप अनुमति दें तो मैं माननीय सदस्य के इस प्रश्न का भी उत्तर दे सकता हूं।

श्री सभापति: सदस्य जवाब चाहते हैं तो आप दे दें।

श्री राजनाथ सिंह: सभापति महोदय, यह प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। जिसे हम

गोल्डन क्वॉड्रिलैटरल यानी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के नाम से जानते हैं। उसी के साथ नार्थ से साउथ का और ईस्ट से वेस्ट को जोड़कर एक कॉरीडोर बनाने की भी योजना है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अन्तर्गत भारत की राजधानी दिल्ली को मुम्बई, चेन्नई और कलकत्ता से जोड़ने की योजना है और यह छह हजार किलोमीटर का पूरा मार्ग होगा। इसको चार से छह लेन का सड़क मार्ग बनाने की योजना है। इस पर कार्य तो प्रारम्भ हो चुका है। जहां तक मुझे जानकारी है कि 1200, 1300 किलोमीटर की सड़क का निर्माण हो चुका है।

श्री ओंकार सिंह लखावत: नहीं, मंत्री महोदय, आपने चार दिन पहले कहा कि 230 किलोमीटर का निर्माण हुआ है। कृपया आप देख लें, आपने और आपके मंत्रालय ने ही यह उत्तर दिया है।

श्री राजनाथ सिंह: सभापति महोदय, यह मूल प्रश्न से संबंधित प्रश्न नहीं है। लेकिन मुझे जो जानकारी है वह यह है कि 1000, 1200 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो चुका होगा अथवा कांट्रेक्ट अवार्ड किया जा चुका होगा।

सभापति महोदय, यदि यह मूल प्रश्न होता तो मैं निश्चित रूप से पूरी तैयारी के साथ आता। लेकिन मैं माननीय सदस्य को जरूर आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो समय निर्धारित है, उस समय तक निश्चित रूप से इस परियोजना का काम अवश्य पूरा हो जाएगा।

SHRI JANARDHANA POOJARY: Sir, my supplementary question arises out of the reply given by the hon. Minister just now. I would like to know from the hon. Minister whether he is getting any assistance from any multinational companies or any foreign assistance, including the World Bank, for this dream project which he has mentioned just now. If so, to what extent is it?

श्री राजनाथ सिंह: ऐक्सटर्नल एजेंसिस के माध्यम से भी हम असिस्टैंस प्राप्त कर रहे हैं। पूरी जानकारी के लिए पहले मुझे मेरे विभाग से जानकारी लेनी पड़ेगी लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, 400 करोड़ रुपया प्रति वर्ष वर्ल्ड बैंक से प्राप्त होगा। लेकिन इस समय इकॉनॉमिक सैंक्शन लगा हुआ है। वार्ता हो चुकी है, नैगोसिएशन का काम पूरा हो चुका है लेकिन इकॉनॉमिक सैंक्शन होने के कारण अभी तक वह धनराशि हमें प्राप्त नहीं हो सकी है। मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं ताकि पूरा सदन भी इस बात से अवगत हो जाए कि इस पूरी परियोजना के निर्माण में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी, उसकी पूरी व्यवस्था हम लोगों ने सुनिश्चित कर ली है।

SHRI M.J. VARKEY MATTATHIL: Mr. Chairman, Sir, we are discussing about the golden quadrilateral road for India. I wonder why Kerala State has not been included in this golden quadrilateral. Primarily, I would say that Kerala is an important State. So, why was it not included? In the whole of the

Southern corridor, from Bangalore, Madras to Bombay, Kerala, is one of the important States, as it exports cash crops such as, cashew, black-pepper, rubber, copra, etc. I would like to know from the hon. Minister why Kerala State, and the Western corridor stretching from Kanyakumari, Trivandrum, Cochin, Calicut, Mangalore, Goa to Maharashtra, was left out? I would like to know from the hon. Minister as to why he did not think about it. It is a request by an MP from Kerala. We feel very bad about it. I request the hon. Minister to give a favourable reply.

श्री राजनाथ सिंह: सभापति महोदय, मैं फिर से निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है फिर भी मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि केरल जैसे ब्यूटीफुल स्टेट की उपेक्षा कभी भी हमारा मंत्रालय और हमारी सरकार नहीं कर सकती है लेकिन जो यह प्रोजैक्ट बनाया गया है, उसमें इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि किस मार्ग पर ट्रैफिक डैंसिटी अधिक है—इस आधार पर यह किया गया है। इसमें रीअलाइनमेंट फिलहाल संभव नहीं है।

श्री नरेन्द्र मोहन: सर, अभी जो आर्थिक समीक्षा प्रकाशित हुई है इसमें इस विषय पर विस्तार से जानकारी दी गयी है। जो सुप्रीम चतुर्भुज या राजमार्ग है, उसके बारे में चर्चा की गयी है। इस संबंध में मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने राज्यों से बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं? क्या सभी जगह पर्याप्त रूप से भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है और कहां क्या कठिनाई हो रही है? इसके अतिरिक्त आपके पास जो धन आबंटित हुआ है, उससे आप कितना कार्य इस वर्ष पूरा कर लेंगे? आखिर इस वर्ष भी आपकी जो योजना थी वह लगभग 1200 किलोमीटर की थी। आपने बताया है कि 504 किलोमीटर राजमार्ग पहले बन चुका है, इसके अलावा 1200 किलोमीटर और बनना है। यह जो 1200 किलोमीटर और बनना है, इसमें कौन-कौन से राज्य और जुड़ जाएंगे, क्या स्थिति होने वाली है, यह बताने का कष्ट करें।

श्री राजनाथ सिंह: सर, मैं पुन: अनुरोध करना चाहता हूं कि यह प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है ...(व्यवधान)...

श्री नरेन्द्र मोहन: आपने उसको खोल दिया ...(व्यवधान)...

श्री राजनाथ सिंह: खोलने का प्रश्न नहीं है। ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य जो जानकारी चाहते हैं या तो मैं इस संबंध में सीधा कह देता कि मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा लेकिन माननीय सदस्य ने जो स्पैसिफिक जानकारी मांगी है, वह स्पैसिफिक जानकारी तो फिलहाल मेरे पास नहीं है लेकिन माननीय सदस्य ने जो यह जानना चाहा है कि इस योजना को पूरा करने में किन-किन राज्यों में बाधाएं आ रही है तो जहां तक मुझे जानकारी है—स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को पूरा करने में किसी राज्य में कोई बाधा नहीं आ रही है लेकिन नॉर्थ-साउथ और ईस्ट-वैस्ट जो हमारा कॉरीडोर है, उसमें कुछ स्थानों पर लैंड ऐक्वीजीशन की प्रॉब्लम आ सकती है लेकिन उस लैंड

ऐक्वीजीशन की समस्या का समाधान कैसे होगा, उस पर हम लोगों ने विचार कर लिया है, निर्णय कर लिया है।

†**श्री मोहम्मद सलीम:** सर, प्रश्न के उत्तर का विस्तार किया गया, इस संबंध में मैं कोई स्पैसिफिक आंसर नहीं चाह रहा हूं लेकिन यह जो आप कॉड्रीलैट्रल और नॉर्थ-ईस्ट कॉरीडोर की और साउथ-वैस्ट की बात कर रहे हैं, इसमें जो पुराने शहर थे, उसमें कुछ हैरीटेज सिटीज हैं, कुछ हैरीटेज साइट्स हैं। जब यह योजना बनायी गयी तो इसमें ऐक्सपर्ट्स, का ओपीनियन नहीं लिया गया—ऊपर से सिर्फ दिमाग में आया और अनाउंस कर दिया गया। इसमें हमारी जो हैरीटेज साइट्स हैं—दोनों तरफ से—एक तो पुराने शहारों की कनैक्टीविटी का मामला है और दूसरी तरफ जो इम्पोर्टेंट पिल्लर्स हैं, टाउनशिप्स हैं, उसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचे, इस बारे में आप क्या प्रावधान कर रहे हैं?

श्री राजनाथ सिंह: माननीय सभापति जी, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि बहुत सोच-विचार कर और कंसल्टेंट्स की राय लेने के बाद ही टास्क फोर्स ने इस प्रोजेक्ट के संबंध में अंतिम निर्णय किया है इसलिए यह कहा जाना कि हमने कोई ऐसा फैसला कर लिया है, यह उचित नहीं है लेकिन इस परियोजना को तैयार करते समय यह विचार किया गया था कि जिन मार्गों पर ट्रैफिक डेनसिटी अधिक हो, जहां से आम लोगों का आवागमन ज्यादा होता हो, उसी को लिया जाए। इस आधार पर यह किया गया था और अगर माननीय सदस्य चाहेंगे कि इसके रीएलाइनमेंट के बारे में विचार किया जाए तो मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा कि फिलहाल यह संभव नहीं है क्योंकि परियोजना पर कार्य प्रारंभ हो चुका है।

Cellular Telecom Services

*163. SHRI NILOTPAL BASU:‡
SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the TRAI has referred to cellular telecom services as a premium service and not a utility service in its documents;

(b) if so, the response of Government in accepting this assessment; and

(c) if such a service is indeed a premium service, the reasons for foregoing the deemed payment from private cellular telecoms and going ahead with migration package and claiming this as 'public good'?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI RAM VILAS PASWAN): (a) to (c) A statment is laid on the Table of the House.

†Transliteration of the Speech in Persian Script is available in the Hindi version of the Debate.

‡ The question was actually asked on the floor of the House by Shri Nilotpal Basu.